The International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences
(IJARMS)
Volume 3 Issue 2, Dec. 2020

वैश्विक परिवेश में भारत–चीन संबंधः चुनौतियाँ एवं उभरते मुद्दे

डॉ० भरत कुमार
स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग,
ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

विगत चार दशकों के दौरान चीन महापरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस छोटे से कालखंड में यह विश्व की महाशक्ति भी बन चुका है, और आने वाले वर्ष में वह अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन यह शानदार उभार, अपनी अद्वितीय और आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति–दर, जो पिछले 40 वर्षो से लगातार, बिना लड़खड़ाए 10 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है– के बल पर पहले से ही सुनिश्चित कर चुका है। उसकी शानदार, चमचमाती हुई उपलब्धि का मनुष्यता के ज्ञात इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि चीन के आलोचक भी उसकी इस महान सफलता का लोहा मान चुके हैं। विश्व बैंक ने भी लिखा है कि चीन ने –'इतिहास में सबसे तेज, टिकाऊ और भरोसेमंद प्रगति, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की है। इस अवधि में उसने 80 करोड़ नागरिकों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है।' चीन में बदलाव की शुरुआत 1979 से आर्थिक सुधारों की घोषणा से हुई थी। आज वह 'क्रय–शक्ति तुल्यता' के आधार पर विश्व–भर में पहले पायदान पर मजबूती से डटा है। अनेक अर्थशास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि चीन आगामी दो दशकों में, यहाँ तक कि उससे पहले ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर चुका है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जब भी ऐसा होगा, वह पिछले सौ या फिर उससे भी अधिक वर्षो में अपनी तरह का पहला अवसर होगा, जब विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति की मशाल किसी गैर–यूरोपीय देश के हाथो में होगी।

मुख्य शब्दः– आर्थिक, विश्व, अर्थव्यवस्था, महाशक्ति, प्रगति, विकास, सुधार

प्रस्तावना

माओत्से तुंग की मृत्यु यानी 1976 के बाद, चीन के नए नेतृत्व ने आर्थिक विकास के लिये विकल्पों पर काम करना आरंभ कर दिया। रास्ता आसान नहीं था, परंतु 'चाइनीज कम्यूनिस्ट पार्टी' का सुधारवादी समूह नीतियों की स्पर्धा में माओ के विश्वस्तों को आने वाले वर्षो में किनारे कर देना चाहता था। प्रकारांतर में, 1978 में डेंग जियोपिंग का चीन की राजनीति में सुधारवादी नेता के रूप में उदय हुआ। डेंग 1989 में अपनी रिटायरमेंट तक उस पद पर बने रहे। जियोपिंग ने चीन को आर्थिक सुधारों के लिए नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में दिसंबर 1978 में आर्थिक सुधार के एक कार्यक्रम, 'चीनी लक्षणों से युक्त समाजवाद' (Socialism with Chinese Characteristics) आरंभ किया गया।

जियोपिंग के नेतृत्व में चीन ने सोवियत संघ से मिलती हुई नियंत्रित अर्थव्यवस्था तथा मुक्त बाजार के नियमों के अनुरूप उत्तरोत्तर सुधरती अर्थव्यवस्था जैसी आर्थिक सुधारवाद की अपेक्षाकृत व्यावहारिक नीति लागू की। जियोपिंग ने ठेठ सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के बजाय सहज आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी, जिसे उनके इन शब्दों में समझा जा सकता है– 'काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई बिल्ली जब तक वह चूहे को दबोचती है, उसका रंग कैसा है।' इस तरह 1979 के बाद, सरकार ने अनेक सुधारवादी कार्यक्रम लागू किए, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशियों, विशेषरूप से पश्चिमी देशों के लिए खोल दिए। विशेष छूट, प्रोत्साहन के आधार पर अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया, साथ ही उन्हें क्रमशः बढ़ावा दिया गया।नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे निजी व्यापार की शुरूआत करें। निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करके सरकार ने उसे आसान बना दिया। परिणामस्वरूप बाजार उत्पादन से जुड़े मसलों का नियामक बन गया। कुछ खास उत्पादों को मूल्य नियंत्रण नीति से बाहर निकाल दिया गया। सरकार ने व्यापार को और सरल बनाने के लिए आवश्यक कानून भी बनाए। 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment) हेतु विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु अनेक प्रकार की छूट तथा टैक्स और व्यापार से जुड़ी अनेक सुविधाओं का ऐलान किया गया। इन सुधारात्मक कार्यक्रमों के फलस्वरूप चीन ने टिकाऊ आर्थिक विकास के युग में प्रवेश किया, जिसका सुफल देश के कायाकल्प के रूप में सबके सामने है। 1979 से लेकर 2019 तक चीन के सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) में औसतन 9.6 प्रतिशत वार्षिक की निरंतर स्थायी बढ़त हासिल की गई, जो अपने आप में अद्वितीय थी।

चीनः एक आर्थिक महाशक्ति

चीन के शानदार आर्थिक विकास को लेकर कोई विवाद नहीं है। अगर आँकड़ों की ही बात करें तो 2017 में उसका सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 11,900 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस आधार पर वह विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले स्थान पर अमेरिका आता है जिसका सकल घरेलू उत्पादन 19,3600 अरब डॉलर था। यह अपने आप में प्रभावित करता है, लेकिन इससे तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केवल मुद्रा–विनिमय दर के आधार पर दोनों के जीडीपी की तुलना तथा उसके अनुसार उनके जीवन स्तर की सही तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। मुद्राओं की सामान्य विनिमय दर मात्र संकेतक है, जो अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष बाकी मुद्रा की विनिमय दर को दर्शाती है। केवल मुद्राओं के आपसी विनिमय के आधार पर किसी देश से संबंधित मुद्रा के क्रय सामर्थ्य का आकलन कर पाना संभव नहीं है। चूँकि कम, विकसित देशों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के दाम आनुपातिक रूप से कम होते हैं, जैसे कि दस डॉलर हाथ में हो तो चीन में, अमेरिकी बाजार की तुलना में दो गुने समान की खरीद संभव है।

इस विचलन को ठीक करने अथवा किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्ति के सटीक आकलन हेतु आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्राओं की तुलना, उनकी आपसी विनिमय दर के बजाय, डॉलर के सापेक्ष वास्तविक क्रय–शक्ति के आधार पर करने का समर्थन करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे क्रय–शक्ति समता (Purchasing Powre Parity) कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आँकड़ें बताते हैं कि 2017 में चीन में वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य दर, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में आधी थी। इस आधार पर यदि चीन और अमेरिका की जीडीपी की तुलना की जाए तो चीन की जीडीपी 23,100 अरब डॉलर होगी, जो अमेरिकी जीडीपी से अधिक हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आँकड़े वस्तुतः इसी ओर संकेत करते हैं कि क्रय–शक्ति समता के आधार पर चीन, 2014 में ही, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। यदि चीन की प्रगति दर इसी तरह बनी रही तो सामान्य दरों के अनुसार भी 2030 में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा।

यद्यपि चीन के आर्थिक प्रगति में कुछ वर्षो से गिरावट दर्ज की गई है फिर भी आने वाले दशक में या उससे पहले ही हम चीन को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए देखेंगे। परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाने के कारण चीन के उत्पादन क्षेत्र की जीडीपी में यद्यपि कुछ गिरावट दर्ज की गई है, मगर उसका सेवा क्षेत्र उतनी ही मजबूती और त्वरा के साथ विकासमान है। 2016 की तीसरी तिमाही में चीन के जीडीपी में उसके सेवा क्षेत्र का योगदान 52.8 प्रतिशत था। जबकि उसकी कुल घरेलू खपत का जीडीपी के विकास में 71 प्रतिशत योगदान है। यह माना जाता है कि 2030 तक चीन के सेवा क्षेत्र का योगदान उसके जीडीपी में 70 प्रतिशत हो जाएगा। उस समय तक, तेजी से उभरते मध्यवर्ग के आधार पर चीन की घरेलू खपत 6000 अरब डॉलर को छूने लगेगी, जो विश्व में सर्वाधिक होगी। चीन पहले से ही अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। भारत में चीनी दूतावास के सूचना बुलेटिन' न्यूज फ्राम चाइना' के अनुसार चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की 18 से 24 अक्टूबर 2017 के बीच संपन्न हुई। 19वीं नेशनल कांग्रेस में, चीन के राष्ट्रपति और पार्टी अध्यक्ष झी जिनपिंग ने सदस्यों को संबोधित करते हुए 'चीनी मिजाज के समाजवाद' पर जोर देते हुए कहा था– 'एक आधुनिक समाजवादी देश तथा सभी तरह से सुखी, समृद्ध एव संयमित समाज के निर्माण के लक्ष्य में सुनिश्चित सफलता हेतु उत्पादक शक्तियों का विकास, तथा उन्हें उन्हीं के भरोसे पर खड़ा करना आवश्यक है।' 2050 तक चीन ने जो बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनमें ग्रामीण एवं निर्धन लोगों के जीवन–स्तर में सुधार, आय–असमानताओं (जैसे कि अमीर–गरीब, ग्रामीण–शहरी) को दूर करना, व्यक्तिगत खपत को अर्थव्यवस्था का संचालक बनाना, सेवा–क्षेत्र का विकास, प्रदूषण में कमी, नए शोधों तथा आधुनिकीकरण में तेजी तथा जीवन–स्तर संबंधी सभी मानकों में सुधार सम्मिलित है। चीन द्वारा प्रस्तावित 'एक बेल्ट एक सड़क' योजना तथा दूसरी अन्य पहलकदमियाँ जैसे कि 57 संस्थापक सदस्य देशों के सहयोग तथा 100 अरब डॉलर की पूंजी से, अक्टूबर 2014 में 'एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' की घोषणा, जो जनवरी 2016 से विधिवत अपना काम शुरू कर चुका है– चीन की महत्त्वाकांक्षाओं की उड़ान को दर्शाता है। चीन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संपन्न तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2015 में राष्ट्रपति झी जिनपिंग में 'मेड इन चाइना' अभियान की शुरूआत की थी। यही नहीं चुस्त–दुरुस्त अर्थव्यवस्था तथा पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने, अवसर आने पर उन्हें मात देने के लिए चीन नए–नए क्षेत्रों; तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) आदि में भी भारी–भरकम धनराशि का निवेश कर रहा है।

भारत–चीन संबंध

आर्थिक और सैन्य शक्तियों के रूप में भारत तथा चीन विश्व के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों राष्ट्रों में कई समान विशेषताएँ हैं एवं यहाँ तक कि एक जैसी ही समस्याएँ भी विद्यमान हैं। इनमें विशाल जनसंख्या, वृहद ग्रामीण–शहरी विभाजन, उभरती अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष शामिल है।

भारत व चीन एक लम्बी अवधि से एक दूसरे को सामरिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से पीछे करने के लिए प्रयत्न करते आ रहे हैं तथा एशिया में अपने वर्चस्व को लेकर उलझ रहे हैं। आज के राजनीति में चल रहे संक्रमण काल में भारत–चीन संबंधों की नई पहल का महत्व दोनों देशों के हितों के लिए ही नहीं, अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए आवश्यक है।

भारत चीन संबंधों का विकास

ज्ञातव्य है कि हजारों वर्षो तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण

कर वहाँ कब्जा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए।

- 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे।
- दोनों देशों के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरूआत भारत की स्वतंत्रता (1947) और चीन की कम्युनिस्ट प्रथम क्रांति (1949) के बाद हुई।
- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे, नेहरू जी के इस विचार ने शुरूआती दौर में भारत और चीन के संबंधों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आध्यात्मिक संबंध चीन के लिये चिंता का विषय था।
- वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई ने ‘‘हिंदी–चीची–भाई–भाई के नारे के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किये, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिये कार्य योजना तैयार की जा सके।
- वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमाचली क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया।
- चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 104,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत किया और दोनों देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशेधन की मांग की।
- वर्ष 1962 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाक और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट–फ्रंटियर एजेंसी मे मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों देश के मध्य युद्ध शुरू हो गया एवं संबंध और अधिक खराब स्थिति में पहुँच गए।
- वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के एक नए चरण की शुरूआत की और जिसके माध्यम से भारत और चीन के संबंध पुनः सामान्य होने लगे।

विभिन्न क्षेत्रों पर भारत–चीन संबंध

• राजनीतिक संबंध

भारत ने 1 अप्रैल, 1950 को चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किये थे और इसी के साथ भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश बन गया था। वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष की शुरूआत दोनों देशों के संबंधों के लिये एक गहरा झटका था। परंतु वर्ष 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य समय–समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ–साथ अनौपचारिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देश अपने दीर्घकालिक हितों को लेकर सजग हैं।

• वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध

भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिये भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। भारत और चीन ने बीच व्यापार

और आर्थिक संबंधों मे पिछले कुछ वर्षो में तेजी देखी गई है। वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 3 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो कि वर्ष 2017 में बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

●सांस्कृतिक संबंध

भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान–प्रदान की शुरूआत कई शताब्दियों पहले हुई थी। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मौजूद हैं जो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की शांग–झोउ सभ्यता के मध्य 1500–1000 ई. पू. के आस–पास वैचारिक और भाषायी आदान–प्रदान को दर्शाते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक 'रेशम मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रा की। इसी तरह कई चीनी यात्री जैसे– इत्सिंग, फाह्यान और हवेनसांग आदि भी भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा शैक्षणिक आदान–प्रदान हेतु वर्ष 2003 में पेकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई थी। चीन में भी योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सह–प्रायोजकों में चीन भी एक था। भारतीय फिल्में भी चीन में काफी लोकप्रिय हैं और वहाँ काफी अच्छी कमाई करती है।

●शैक्षिक संबंध

भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम (EEP) पर हस्ताक्षर किये, ज्ञातव्य है कि यह दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत भारत और चीन एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा मान्यता प्राप्त संस्थानों के 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के परिणामस्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। आँकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2016–17 के दौरान चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 18171 भारतीय छात्र विभिन्न विषयों में अध्ययनरत थे।

भारत–चीन संबंध–चिंताएँ

तिब्बत और दलाई लामा

- उल्लेखनीय है कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव ही काफी संवेदनशील रहा है। तिब्बत पर भारत का शुरूआती पक्ष और भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना ऐतिहासिक रूप से चीन के लिये चिंता का विषय रहा है।
- वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और पंडित नेहरू ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया था।
- चीन दलाई लामा (जिनका तिब्बतियों पर गहरा प्रभाव है) को अलगाववादी मानता है।
- तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकन चीन का रवैया हमेशा से आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार समूहों ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है।

सीमा विवाद

- भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद भी है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना–अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, ज्ञातव्य है कि वर्तमान में अक्साई चीन, चीन के पास है, जबकि अरूणाचल प्रदेश भारत के पास।

- मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित करना भी था।

डोकलाम विवाद

भारत–भूटान करारः– डोकलाम विवाद में भारत की ताजा भूमिका भारत–भूटान के बीच हुई रक्षा संधि की वजह से है। इस संधि के तहत भूटान की रक्षा एवं विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भारत की है। यह संधि दोनों देशों के लिये फायदेमंद है। डोकलाम में भारत के हस्तक्षेप पर चीन, भूटान पर दबाव डालता है तो भूटान रक्षा संधि का हवाला देकर चीन की नाराजगी से बच जाता है और चीन से उसे कोई सीधी बातचीत नहीं करनी पड़ रही है। वहीं भारत इस संधि का हवाला देकर डोकलाम में अपनी उपस्थिति को जायज ठहरा रहा है। चीन ने भी इस संधि पर कोई आपित्त नहीं की है क्योंकि अतीत में भूटान, सिक्किम ब्रिटिश भारत के संरक्षित राज्य रहे हैं।

चीन यह स्वीकार करता है कि डोकलाम विवादास्पद इलाका है लेकिन विवाद भूटान के साथ है पर भूटान कहता है कि रक्षा नीति भारत के द्वारा संचालित है। संधि के तहत ही भारतीय सेना की एक टुकड़ी भूटान में रहती है। इस पर भूटान सरकार या जनता को कोई आपत्ति नहीं हैं। भूटान की सरकार और जनता का भारत को पूरा समर्थन प्राप्त है। भूटान के वर्तमान राजा और प्रधानमंत्री की शिक्षा–दीक्षा भारत में ही हुई है। जनता के बड़े हिस्से में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हालांकि एक छोटे समूह मे भारत के प्रति विरोध हो सकता है। जिसका मकसद भारत के साथ–साथ वहां के राजा की छवि खराब करना भी है। यह समूह चीन जैसे देशों के द्वारा स्पोंसर (प्रायोजित करना) है। चीन का भारत के प्रति रवैया प्रारंभ से ही शत्रुतापूर्ण रहा है। चीन मानता है कि एशिया में यदि उसे कोई चुनौती दे सकता है तो वह भारत ही है। हमने चीन को ठीक से समझने मे प्रारंभ में की कई ऐतिहासिक भूलें की हैं। तिब्बत ऐसी भूल का एक उदाहरण है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत देश में कुछ लोग व्यापारिक संबंध खत्म करने की मांग कर रहे हैं लेकिन हमे यह याद रखना होगा कि व्यापारिक संबंध एक दिन में खत्म नहीं किए जा सकते हैं। वैश्विक तौर पर देखें तो वर्तमान में अमरीका भी चाह कर चीन से अपने व्यापारिक संबंध जल्दी खत्म नहीं कर पा रहा है। फिर भारत का चीन से व्यापार पिछले कुछ साल में काफी बढ़ गया है। देश में चीन के ऐसे उत्पादों की भरमार है जिसे आम जनता हाथो–हाथ ले रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इन उत्पादों से जुड़ी है। ऐसे में अचानक व्यापार खत्म नहीं हो सकता है।

जल विवाद

- भारत और चीन के बीच जल विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है जो दोनों देशों से होकर बहती है।
- बीते कुछ वर्षो में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि चीन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बांध का निर्माण कर रहा है और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, यही दोनों पक्षों के मध्य विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

दक्षिण चीन सागर का मुद्दा

- चीन, दक्षिण चीन सागर के 90 प्रतिशत हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

- चीन, ताइवान और वियतनाम स्प्राटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। विदित हो कि स्प्राटल, दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपसमूह हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत वियतनाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा हैं।

भारत और चीन–सहयोग क्षेत्र

- दोनों देशों के मध्य प्रतिद्वंदिता के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक स्तर पर काफी अच्छा सहयोग किया है, उल्लेखनीय है कि भारत में जन्मा बौद्ध धर्म चीन में काफी लोकप्रिय है।
- दोनों ही देश दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (BRICS) का हिस्सा हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 में ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई (चीन) में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के वी कामथ (एक भारतीय) है।
- ज्ञातव्य है कि भारत चीन समर्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य भी था।

भारत की विदेश नीति और चीन

भारत ने चीन से निपटने के लिये दोतरफा नीति अपनाई है। इस नीति के तहत एक ओर भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिये ब्रिक्स, एससीओ (SCO) तथा रुस–भारत–चीन त्रिपक्षीय जैसे मंचों से लगातार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत में अपनी सैन्य और निवारक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों को नीति के दूसरे पक्ष के रूप में कायम रखा है।

व्यापार घाटा–एक बड़ी चिंता

बीते दो दशकों में भारत और चीन के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ एक ओर वर्ष 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार सिर्फ 3 बिलियन डॉलर था, वही वर्ष 2008 में यह बढ़कर 51.8 बिलियन डॉलर पहुँच गया। इस प्रकार चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा साझेदार बन गया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में दोनों देशों का कुल व्यापार 95.54 बिलियन डॉलर का था, परंतु इसमें भारत द्वारा कुल निर्यात मात्र 18.84 बिलियन डॉलर का था अर्थात् चीन ने भारत से जितना सामान खरीदा उससे पाँच गुना सामान बेचा। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा भी चीन के साथ ही है, वर्ष 2018 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 57.86 बिलियन डॉलर का था।

धारा 370 और चीन

कश्मीर को लेकर चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाया जाना चाहिये। कुछ ही महीनों पूर्व जब जम्मु कश्मीर की विशेषाधिकार संबंधी धारा 370 को निरस्त किया गया था, तब चीन का कहना था कि भारत ने चीन की संप्रभुता संबंधी चिंताओं का उल्लंघन किया है। चीन की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह लद्दाख पर अपने दावे को दोहरा रहा था। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन ने कश्मीर और धारा 370 का विषय संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उठाया था और कहा था कि हम जम्मू–कश्मीर की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

चीन का हॉन्गकॉन्ग संकट और भारत

भारत का रुख चीन की हॉन्गकॉन्ग नीति के प्रति उदासीन रहा है। भारत ने कभी प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया है, जबकि अन्य देश खुलकर हॉन्गकॉन्ग के लोगों का समर्थन करते रहे हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेदों को बढ़ाना नहीं चाहता है किंतु चीन का रूख कश्मीर जैसेमुद्दे पर भारत विरोधी ही रहा है। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, वहीं स्वयं उईगर तथा हॉन्गकॉन्ग के मामले में अमानवीय रुख अख्तियार करता है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिये। यदि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी हॉन्गकॉन्ग का खुलकर समर्थन करना चाहिये।

वन बेल्ट वन रोड (OBOR) और भारत

वल बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गो के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है, परंतु भारत अब तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की OBOR पहल में चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को भी शामिल कर लिया गया है। चूँकि CPEC गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः OBOR में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर देना, जो भारत की संप्रभुता के लिये खतरा है। इसके अलावा OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात (Project Export) का माध्यम है जिसके जरिये वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के विकास के लिये कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में नहीं होगा।

भारत और चीन के मध्य सहयोगः

- दोनों राष्ट्र उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य हैं। BRICS द्वारा औपचारिक रूप से ऋण देने वाली संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है।
- चीन समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है।
- दोनों पक्ष शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत निरंतर सहयोग के लिए तैयार हैं। चीन ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की पूर्ण सदस्यता का स्वागत किया।
- दोनों देश विश्व बैंक तथा IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोकतांत्रिकरण के समर्थक हैं।
- WTO की वार्ताओं के दौरान चीन और भारत द्वारा समान रुख अपनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की दोहा दौर की वार्ता में कई मुद्दों पर भारत और चीन के दृष्टिकोण समान हैं।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार के पक्ष में हैं। इन सुधारों में इस तथ्य को मान्यता देना शामिल हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मामलों तथा उसके प्रशासनिक ढाँचे में विकासशील देशों की भागीदारी में वृद्धि अनिवार्य है। दोनों देशों का मानना है कि इससे संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकेगी।
- भारत एवं चीन जी–20 समूह के सदस्य हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो।
- दोनों देशों के संबंधों में समानता स्थापित के लिए आर्थिक सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरुआत करना आवश्यक है।
- दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग उन्हें वैश्विक प्रभावों को पुर्नसंतुलित करने और विश्व में एक बेहतर समझौता वार्ता स्तर को विकसित करने में समर्थ कर सकता है।
- चीन और पाकिस्तान पर भारत की विदेश नीति के निर्माण और दृष्टिकोण को अलग–अलग विदेश नीति नियोजन क्षेत्र के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक हाइफेनेटेड (सामासिक) रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए।
- अब समय आ गया है की भारत जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर चीनी आर्थिक शोषण के विरूद्ध विकल्पों को बढ़ावा दे।
- उपमहाद्वीप में कमजोरी स्थिति भारत की कूटनीति का एक गंभीर दोष है।
- भारत के पड़ोसी देशों में से अधिकांश देश भारत के कथित ''नेतृत्व के खिलाफ ''चीन कार्ड' खेलने में माहिर हैं और चीन अपने फायदे के लिए इसका लाभ उठाने के लिए तत्पर है।
- इसकी रणनीति उपमहाद्वीप में भारत को सीमित रखने की है, किन्तु भारत पड़ोसियों के साथ सीमा पर बाड़ की मरम्मत करके तथा उन्हें यह समझा कर कि भारत का उद्देश्य प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, चीन की इस रणनीति से निपट सकता है।

निष्कर्ष

चीन व भारत विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों व विश्व की शांति व विकास के अनेक काम किये हैं। चीन और उसके सब से बड़े पड़ोसी देश भारत के बीच लंबी सीमा रेखा है। वैश्विक ताकत बनने के अपनी महत्त्वाकांक्षा को सबल देने के लिए भारत को ऐसी सैन्य क्षमता विकसित करने की जरूरत है जिसका प्रभाव अपने क्षेत्र से बाहर तक हो। हालांकि इसकी नौसेना पहले ही दूर–दूर तक अपनी छाप छोड़ चुकी है। हमारे देश पर चीन तीन अलग–अलग रास्तों के जरिए सामरिक दबाव बढा रहा है। यह देखते हुए कि चीन समझौते के लिहाज से क्षेत्र में यथास्थिति बरकरार रखने का इच्छुक नहीं है, भारत को ज्यादा यथार्थवादी, नवीनीकृत और कारगर सोच अपनानी होगी।

भारत–चीन सम्बन्धों में सुधार करने के लिए आवश्यक है कि दोनों देश अतीत के पदों को भूलकर एक नए अध्याय का आरंभ व्यापार, व्यवहार एवं विश्वास के साथ करें, आशंकाओं एवं सन्देहों को दर–किनार कर सामरिक सतर्कता के साथ सम्बन्धों को पड़ने पर बल देने की सामयिक आवश्यकता है, यद्यपि हमारे चीन के साथ अनेक मुद्दों पर विरोधाभास है, जैसे भारत में सिक्किम विलय को मान्यता न देना, दोनों देशों के बीच अणु अप्रसार सन्धि, दलाईलामा का भारत में प्रवास, पाकिस्तान के प्रति उसका विशेष व हथियारों की आपूर्ति तथा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के सन्दर्भ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया में जो स्थिति है, इसमें दोनों देशों को अपने क्रियावादी रूख का परित्याग करना होगा और संबंधों के सन्दर्भ में ठोस पहल करनी होगी।

संदर्भ सूची

1. पुष्पेश पंत (2017), भारत–चीन संबंध चुनौतियाँ और उभरते मुद्दे, मैक मिलन प्रकाशन, नई दिल्ली
2. आलम, मुहम्मद बी. (2015): इंडिया, चाइना एंड न्यूक्लियर डील रिफेरेन्स प्रेस, नई दिल्ली

3. चोपड़ा, वी. डी (2003): न्यू ट्रेन्डस इन इंडो चाइना रिलेशन, कल्पज प्रकाशन, नई दिल्ली
4. गुजराल, आई. के. (2003): कानटिन्यूटी एंड चेंज, इंडियाज फॉरेन पालिसी, मैकमिलन प्रकाशन, दिल्ली
5. राय, जयंता के. (2005): इंडिया एंड चाइना एन ऐरा ऑफ ग्लोबिलाईजेशन, बुकवेल प्रकाशन, नई दिल्ली
6. राजन, एम.एस. (1999): इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स लॉसर प्रकाशन, नई दिल्ली
7. खिनानी, आर. के. (2000) रिस्ट्रक्चरिंग इंडियाज फोरेन पालिसी, कॉमनवेल्थ प्रकाशन, नई दिल्ली
8. आलम, मुहम्मद बी. (2013) इंडो चाइना रिलेशनः डाइमेन्शन एंड इमरजिंग ट्रेन्ड, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
9. जयापालन एन. (2001): फॉरेन पालिसी ऑफ इंडिया, अटलांटिक प्रकाशन, नई दिल्ली
10. नितिन पाई, गुप्ता शेखर (2018): स्विंग पावर ऑफ इंडिया एंड चाइना, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली